ASHOKA
SMA - Ashoka Express Publication

अशोका एक्सप्रेस

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक
Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress
E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress
संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 29 ● अंक : 31 ● नई दिल्ली ● 23 से 31 अगस्त 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

'फुटेज खाने की भूख': राहुल गांधी के धरने पर भड़के नड्डा; कहा- सुप्रीम कोर्ट की जांच के बीच प्रदर्शन क्यों?

बगरू स्कूल हिंसा: सीजेपी का शिक्षा मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

जयपुर । जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच शुक्रवार सुबह भारी बवाल हो गया। स्कूल की जर्जर हालत का सच उजागर करने पहुंची सीजेपी टीम पर उग्र ग्रामीणों ने कथित तौर पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस अचानक हुए हिंसक हमले में सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के कपड़े फाड़ने, एक कार्यकर्ता का हाथ तोड़ने और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर करने का आरोप है। इस संघर्ष के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है।

सीजेपी प्रवक्ता को पीटा, अभिजीत दीपके बोले- मारपीट करने वाले गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं जयपुर आऊंगा

भैंसों के तबेले में स्कूल चलाने का आरोप

इस पूरे विवाद की जड़ में रामपुरा कंवरपुरा का वह बदहाल प्राथमिक स्कूल है, जो अपनी जर्जर स्थिति के कारण पिछले काफी समय से एक पशु बाड़े में टीनशेड के नीचे संचालित किया जा रहा है। स्कूल के मुख्य भवन की छत की पट्टियां टूट चुकी हैं, जिन्हें लोहे के भारी एंगलों के सहारे रोका गया है। इस जानलेवा खतरे के चलते स्कूल भवन को बंद कर उसे 50 मीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया था, जहां मासूम बच्चे मवेशियों के चारे और असुरक्षित कच्ची दीवारों के बीच पढ़ाई करने

को मजबूर हैं। पिछले साल के निरीक्षण के दौरान भी स्कूल की यही भयावह स्थिति पाई गई थी।

ट्रैक्टरों से नाकेबंदी और सुबह ग्रामीणों का तांडव

निरीक्षण की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने सुबह 8 बजे से ही बगरू में मोर्चाबंदी कर दी थी। उन्होंने मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर नाकेबंदी कर दी और आने-जाने वाले वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची, तो एक सोची-समझी साजिश के तहत उग्र भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी-डंडों से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया, उनके मोबाइल छीनकर तोड़ दिए गए और एक महिला कार्यकर्ता के साथ भी बदसलूकी की गई। इस पथराव में पीछे छूटे एक कार्यकर्ता को भीड़ ने घेरकर बेरहमी से पीटा।

शिक्षा मंत्री को 48 घंटे की कड़ी चेतावनी

इस हमले के बाद सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इसे राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का 'काला दिन' बताते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मांग की है कि कथित हमले में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और स्कूलों में प्रवेश पर प्रतिबंध का तानाशाही आदेश वापस लिया जाए। रांका ने चेतावनी दी कि यदि समय सीमा में मांगें पूरी नहीं हुईं, तो सीजेपी मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

घटना के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए सवाल उठाया कि भाजपा के गुंडे कार्यकर्ताओं के खून के प्यासे कैसे हो सकते हैं और राजस्थान पुलिस मूकदर्शक क्यों बनी रही। वहीं, भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद ने इस घटना की तीखी निंदा करते हुए कहा कि सरकार स्कूलों की बदहाली को छुपाने के लिए अपने लोगों के जरिए सच की आवाज को दबा रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी इस हिंसक घटना और सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में मीडिया व आम जनता के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध की कड़ी आलोचना की।

''वंदे मातरम' पर राजनीति छोड़ सरकारें बेरोजगारी-बाढ़ पर ध्यान दें', मायावती ने नेताओं को दिखाया आईना!

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि 'वंदे मातरम' पर जारी सियासत ठीक नहीं है और केन्द्र व सभी राज्य सरकारों तथा राजनैतिक दलों को अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिये। मायावती ने शुक्रवार को 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, ''देश में वंदे मातरम् को पूरा गाना है या शुरुआती दो अंतरे गाने हैं या नहीं गाना है, इसको लेकर जो राजनीति चल रही है, वह ठीक नहीं है।'' उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् गायन को लेकर हाल में संसद में जो

कानून पास किया गया है वह बदलाव का कोई पहला मामला नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा कि '' केंद्र और राज्यों में सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ या फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसा करती रहती हैं, यानी एक-दूसरे के बनाए कानूनों को बदलती रहती हैं।'' मायावती ने कहा कि इस समय देश और जनहित के कई अहम मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, '' बेरोजगार युवाओं, छात्र-छात्राओं 'जेन-जी' और स्कूली बच्चों 'जेन-अल्फा' के मुद्दे तथा देश के कुछ हिस्सों में आई भयंकर बाढ़ से हो रही जान-माल की हानि जैसे अनेक अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों को समुचित ध्यान देना चाहिए।'

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द

नई दिल्ली । तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द हो गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को यूएस जाने की मंजूरी नहीं दी है. रेड्डी अभी लंदन में हैं और वे यूएस जाने और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटने का प्लान बनाया था. अब वह अमेरिका नहीं जाएंगे और लंदन से ही हैदराबाद लौटेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, उनकी वापसी 23 अगस्त को हो सकती है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएमओ ने कहा, 'मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में आधिकारिक तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल को विदेश मंत्रालय

की तरफ से अनुमति देने से इनकार करने के बाद अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.'' रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे. उनके च दौरे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावात्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल से जुड़े कार्यक्रम शामिल थे. उन्हें एमिरेट्स स्टेडियम में EPL फुटबॉल से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल होना था. इसके बाद 24 अगस्त को उनका अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT जाने का कार्यक्रम था. 25 अगस्त को बोस्टन में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की टीम से बातचीत और 26 अगस्त को न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के स चैप्टर के एक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना थी.

दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन मामले में दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली । राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार एक मामले में शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। शिकायत की जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप इस मामले में नया केस दर्ज किया जा सकता है या नहीं। पुलिस फिलहाल शिकायत के तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के धरने को लेकर कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता फिलहाल संसद मार्ग पुलिस थाने में धरने पर बैठे हैं। यह मामला सीधा और स्पष्ट है। रोहतक जिले के रहने वाले साहिल के साथ 20 जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गैरकानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। जयराम रमेश ने कहा कि साहिल की एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई है और उसके पूरे शरीर पर पेलेट गन से लगी चोटों के निशान हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ साहिल, उसकी मां और उसके वकील की मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। यह कोई सामान्य एफआईआर नहीं है, बल्कि साहिल के खिलाफ कथित गैरकानूनी पुलिस कार्रवाई और पेलेट गन के इस्तेमाल से संबंधित एक विशिष्ट एफआईआर है। उनकी मांग है कि एफआईआर दर्ज कर उसका पंजीकरण नंबर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले दो घंटे से यह मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

'पीएम ने देश को गरीब बनाया': केजरीवाल बोले- भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम

दिल्ली । भारत की प्रति व्यक्ति आय को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर फिर से हमला किया है। केजरीवाल ने हाल ही में एक पोस्ट साझा कर भारत की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आगे कहा कि देश ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर देश बनाने के लिए चुना था। परंतु, उनके कार्यकाल में भारत बांग्लादेश से भी गरीब हो गया है।

इंडिगो वेबसाइट हफ्ते में दूसरी बार ठप, टिकट बुकिंग अटकी

नई दिल्ली ।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वेबसाइट शुक्रवार को फिर ठप हो गई। कुछ यात्री वेबसाइट से फ्लाइट बुक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ यूजर्स को मोबाइल एप में लॉगिन करने में भी दिक्कत आ रही है। वेबसाइट पर फ्लाइट बुकिंग खोलने पर नो डेटा अवलेबल का मैसेज दिख रहा है।

यह इस हफ्ते दूसरा मौका है जब इंडिगो की वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज में गड़बड़ी आई है। एयरलाइन ने वेबसाइट पर सर्विस एडवाइजरी जारी कर कहा कि सिस्टम में रुक-रुककर दिक्कत आ रही है। इससे कुछ कस्टमर्स को हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है। हमारी टीमें इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही हैं। इंडिगो ने यात्रियों से कुछ समय बाद डिजिटल चैनल दोबारा इस्तेमाल करने को कहा। इंडिगो ने कहा कि जिन ग्राहकों को तुरंत यात्रा संबंधी मदद चाहिए, वे कस्टमर्स सपोर्ट हेल्पलाइन से संपर्क करें। जिन कस्टमर्स की यात्रा बाद में है, वे कुछ समय बाद कोशिश करें। शुक्रवार को कई यूजर्स ने इंडिगो के एक्स अकाउंट पर शिकायतें कीं। इनमें फ्लाइट बुकिंग फेल होना, वेब चेक-इन में दिक्कत और पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं मिलना शामिल था। यह गड़बड़ी उस समस्या के दो दिन बाद सामने आई, जिसे इंडिगो ने अपने मुख्य रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म में माना था।

'दिमागी नक्सलियों' को चाहिए कमजोर लोकतंत्र

ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 'नक्सलवादी', जो नक्सलवादी चारू मजूमदार की बायोपिक के रूप में बनाई गई थी, से लेकर हाल ही में बनी 'लाल सलाम' और 'टैंगो चार्ली' तक सैंकड़ों ऐसी फिल्में बनीं, जिनमें हथियारबंद नक्सलियों के पक्ष में नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। एक ओर पुलिस खलनायक के रूप में दिखती, दूसरी तरफ राजसत्ता आमजन के दुश्मन के रूप में और नक्सलवादी हालात के मारे एकमात्र उद्धारक के तौर पर। विभिन्न भाषाओं में हजारों नाटक आपको नक्सलियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते दिखते रहे होंगे। साहित्य की ओर झांकें तो 'हजार चौरासीवें की मां' से लेकर 'नृशंस' तक लाखों पन्ने आपको मिल सकते हैं, जिनमें एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हथियार उठाने के नक्सली संघर्ष को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की जाती रही। ये लेखक, फिल्मकार, विचारक और रंगकर्मी जंगलों में हथियार के साथ तो नहीं दिखते, नक्सलियों के उन दस्ते में भी नहीं दिखते जो अस्पताल और ट्रेन उड़ाने जाते रहे हैं। ये हमारे-आपके पड़ोस में दिखते हैं, ये विश्वविद्यालयों में दिखते हैं, ये हवाई जहाज पर दिखते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये विदेशों में व्याख्यान देने जाते हैं। राजसत्ता पर 'अधिकार' करने की लड़ाई नक्सली हथियारों के साथ लड़ते हैं, ये सभ्य समाज के बीच उनके पक्ष में नैरेटिव बनाकर उनके मनोबल को बनाए रखने का काम करते हैं। ये समाज को बदलने के झूठे सब्जबाग, जिसके बारे में इन्हें पता है कि ये कभी साकार नहीं हो सकता, दिखाकर युवाओं को सीधे संघर्ष में उतरने को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सही कहा, ''माओवाद ने लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशकों तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को बंदूक की नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थीं और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में सुरक्षा बल के 3500 से ज्यादा जवान शहीद हो गए।''सीधी लड़ाई तो बंदूकों से लड़ी जा सकती है, ऐसी लड़ाई, जिसे दुश्मन हमारी बगल में बैठ कर हमारे ही संसाधनों से लड़ रहा हो, वहां मुकाबला मुश्किल हो जाता है। तब और भी, जब आपको उस नैरेटिव की लड़ाई के लिए तैयार होना हो, जो देश में 80 वर्षों से अपने पंजे और दांत हर दिन हर पल मजबूत करने में लगी है। जाहिर है, प्रधानमंत्री को स्वाधीनता दिवस के भाषण में दिमागी नक्सली को आइसोलेट करने की बात कहनी पड़ती है। गौरतलब है कि इनकी ये गतिविधियां बीते 14 वर्षों से नहीं, हर सरकारों के समय जारी रही हैं, चाहे इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी या फिर आज नरेन्द्र मोदी। इसीलिए यदि किसी राजनीतिक पार्टी, जिसे लोकतंत्र और भारत की संप्रभुता में विश्वास है, को यदि यह भ्रम है कि ये 'दिमागी नक्सली' उनके पक्ष में हैं तो यह भ्रम साफ कर लेना चाहिए। वास्तव में ये मौके की तलाश में रहते हैं। वास्तव में दिमागी नक्सली ही नहीं, हर वामपंथी आंदोलन के दो चेहरे होते हैं, एक जो लोकसभा, विधानसभा में दिखाई देते हैं, उनका लक्ष्य राजसत्ता पर अधिकार और अंततः तथाकथित साम्यवाद के नाम पर देश के तमाम संसाधनों पर अधिकार का होता है। यह साम्यवाद ऐसा है, पूरी दुनिया में अब जिसकी कल्पना तक नहीं की जाती लेकिन भारत में दिमागी नक्सलियों ने अपने स्वार्थ में इसे बचाए रखा है। वास्तव में इनकी लड़ाई भारत की हर मजबूत सरकार से है। इन्हें हमेशा एक कमजोर लुंजपुंज सरकार चाहिए होती है, ताकि देश भारत के संविधान से नहीं, इनकी मर्जी से, इनकी सहूलियतों से चलता रहे। नक्सली जब बिहार में स्कूल और अस्पताल उड़ा रहे थे, तब एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से मैंने पूछा था, यह तो आम जन के उपयोग की चीज है, इसे क्यों ध्वस्त किया जा रहा है? उन्होंने कहा था, आम जनता को सहूलियत मिल जाएगी तो क्रांति कौन करेगा। दिमागी नक्सली यही चाहते हैं, जनता कष्ट में रहेगी, शासन व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी तो देश को अपने अनुसार चलाना आसान रहेगा। वास्तव में दिमागी नक्सल एक सुविधाभोगी प्रजाति है, उसे ए.सी. चाहिए, बंगला चाहिए, लंबी गाड़ी चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए। इस सबके लिए वे कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं, अपने कामरेडों को भी, जिन्होंने जंगलों में जान गंवा दी, संविधान को भी, स्वतंत्रता को भी, देश को भी। ये हर उस स्थिति के साथ होते हैं, जो देश के विरुद्ध होती है, चाहे वह आतंकवाद हो, कश्मीर हो, सियाचिन हो। ऐसा तब आसान हो जाता है, जब देश में अस्थिरता, अराजकता और कमजोर शासन व्यवस्था रहती है। दुनिया के कई देशों की भी इच्छा भारत को इसी अस्थिरता में देखने की होती है। प्रधानमंत्री ने गलत नहीं कहा, हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं। हिंसा, अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति-भांति के दांव लगा रहे हैं।

सम्पादकीय

बदली तकदीर

प्रत्येक नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अनिवार्य आवश्यकताओं में है। यदि ये तीनों चीजें लोगों के पास होंगी तो निश्चित ही उनका गुजर बसर आसानी से हो सकेगा। लेकिन देश एवं प्रदेश में कुछ ऐसे गरीब असहाय परिवार थे जिनके पास अपने परिवार के लिए पक्का मकान नहीं था। गरीबी और निर्धनता के कारण वे अपना आशियाना बनाने में असमर्थ थे और उनका परिवार झोपड़ पट्टी व कच्चे मकान में रहने के लिए विवश था। बिना आवास वाले गरीबों के दुःख-दर्द को दृष्टिगत रखते हुए मा0 प्रधानमंत्री जी ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' पूरे देश में लागू की जो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से गरीब, असहाय लोगों को आशियाना उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक इस योजना से प्रदेश में लाखों बेघरों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आवास विहीन लोगों के सपनों को साकार किया है। लाभार्थियों द्वारा भी सरकार की कोटि-कोटि प्रशंसा की जा रही है। इस योजना से उनके जीवन में एक नई सोच का संचार हुआ है और अब उनकी जिन्दगी ही बदल गई है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी जनपद संतकबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर, मोहल्ला जवाहर नगर वार्ड नं 06 के निवासी जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र विश्राम यादव की है। जितेन्द्र कुमार बताते हैं,' हम गरीब है और मेहनत मजदूरी से घर का खर्चा चलाते थे। जब हमारे पास आवास की सुविधा नहीं थी, तो हमें काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। हम अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में निवास करते थे। मकान अत्यन्त जर्जर अवस्था में था। दीवारों में दरारें थीं और छत कभी भी गिर सकती थी। 'सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि अगर हमारा यह मकान गिर गया तो हम कहां रहेंगे। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में उमस लगती थी और सर्दी में ठंड से बचना मुश्किल था। बच्चों के साथ रहना बहुत कठिन था। सीमित आमदनी में घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था, ऐसे में पक्का मकान बनवाने का सोचना भी असंभव था। श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में हमें जानकारी हुई। यह उनके लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आयी। इस योजना का लाभ उठाने हेतु उन्होंने तुरंत आवेदन किया। संबंधित अधिकारियों द्वारा उनका सर्वे किया गया और उन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। स्वीकृति उपरान्त शीघ्र ही उन्हें अपना स्वयं का पक्का मकान निर्मित करने हेतु तीन किस्तों में धनराशि की प्राप्ति हुई। सरकार से मिली धनराशि से जितेन्द्र कुमार ने अपना पक्का मकान निर्मित कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। मजबूत ईंट-सीमेंट की दीवारें, पक्की आरसीसी छत, टाइल वाला फर्श और हवादार कमरे। अब न बरसात का डर है, न आंधी-तूफान की चिंता। जितेन्द्र कुमार कहते हैं, 'पहले लगता था कि जीवन ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन पीएम आवास योजना ने हमें नया जीवन दिया। अब हम सम्मान के साथ रह रहे हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए अलग कमरा है और परिवार चैन से सोता है। आज जितेन्द्र कुमार का परिवार इस योजना से लाभ प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न है। वे कहते हैं कि इस पक्के घर के बाद समाज में हमारी इज्जत भी बढ़ गई है।

बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सशक्त होतीं ग्रामीण महिलाएं

स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेलों, प्रदर्शनियों और विशेष बिक्री केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे ग्रामीण उत्पादों का उचित मूल्य सीधे महिला उत्पादकों को मिल रहा है। आर्थिक स्वावलंबन ने बलरामपुर की महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामूहिकता की भावना का विकास किया है। अब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे पारिवारिक एवं सामुदायिक विषयों पर सक्रिय होकर निर्णय ले रही हैं। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत न होकर पूरे ग्रामीण परिवेश को सकारात्मक दिशा दे रहा है। बलरामपुर जनपद में क्रियान्वित किए जा रहे आजीविका संवर्धन मॉडल से यह स्पष्ट है कि लक्षित वित्तीय सहयोग, संस्थागत मार्गदर्शन और महिलाओं की लगन से किसी भी पिछड़े क्षेत्र का कायाकल्प संभव है। समूह से जुड़ी महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की मूक लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण विकास की कुशल संचालक बन चुकी हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साझा विजन से संचालित यह अभियान ग्रामीण अंचल से गरीबी उन्मूलन और महिला नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' जनपद बलरामपुर में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। सुदूर ग्रामीण अंचलों में निर्धन परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उन्हें आजीविका के अवसरों से जोड़ने के सुनियोजित प्रयास अब धरातल पर व्यापक सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रहे हैं। जनपद बलरामपुर में वर्तमान में 13,524 महिला स्वयं सहायता समूह पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से हजारों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। पारंपरिक रूप से घर की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली यहां की ये महिलाएं आज संगठित होकर वित्तीय प्रबंधन, उद्यमिता और सामाजिक विकास की मुख्य धारा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। जिला प्रशासन के समन्वय से इन स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने के लिए त्रिस्तरीय वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग प्रणाली लागू की गई है। समूहों को रिवाल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि और बैंकों के माध्यम से सुलभ ऋण की सुविधाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वित्तीय समावेशन से ग्रामीण महिलाएं अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए साहूकारों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त होकर आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हुई हैं। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय में स्थायी वृद्धि करते हुए महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में लाना है। इसके लिए प्रति परिवार न्यूनतम एक लाख रुपये की वार्षिक आमदनी सुनिश्चित करने का रोडमैप तैयार किया गया है। वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यम स्थापना के माध्यम से महिलाओं को आय के विविध स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका स्रोतों को बढ़ाने के प्रयासों के तहत कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में विविध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं आधुनिक कृषि पद्धतियों, पशुपालन, डेयरी संचालन के साथ-साथ सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किराना व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय हस्तशिल्प जैसे सूक्ष्म उद्यमों का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रही हैं। जनपद के सदर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत हंसुआडोल की निवासी शीतला देवी का उदाहरण इस मिशन की सफलता की एक मिसाल है। लगभग दो वर्ष पूर्व स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 70 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त की थी। इस पूंजी से उन्होंने अपने परिवार के सहयोग से किराना दुकान एवं ब्यूटी पार्लर का कार्य प्रारंभ किया। उद्यम में निरंतर प्रगति के उपरांत शीतला देवी ने आधुनिक दोना-पत्तल निर्माण मशीन स्थापित कर अपने व्यवसाय का विस्तार किया। आज उनका उद्यम न केवल उनके पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सफल रहा है, बल्कि उन्होंने गांव के चार अन्य व्यक्तियों को भी अपने यहां नियमित रोजगार उपलब्ध कराया है। शीतला देवी आज पूरे जनपद में एक सफल और अनुकरणीय 'लखपति दीदी' के रूप में पहचानी जा रही हैं। जनपद में स्थापित 13,524 समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों का सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे अंतिम पायदान पर खड़ी महिला तक विकास योजनाओं और वित्तीय सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश स्तर पर शुरू की गई नवाचारी पहलों का भी जनपद में प्रभावी क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। समूह की महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और विद्युत सखी जैसी विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये दीदियां घर-घर जाकर डिजिटल वित्तीय सेवाएं, पेंशन वितरण, छात्रवृत्ति निकासी और बिजली बिल वितरण एवं राजस्व संग्रह जैसे कार्यों का संपादन कुशलतापूर्वक कर रही हैं। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से जहां एक ओर सुदूर ग्रामीणों को उनके घर पर ही पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन सेवाओं से जुड़ी महिलाओं को नियमित लाभांश और मानदेय के रूप में सम्मानजनक आय प्राप्त हो रही है। इससे उनके पारिवारिक निर्णय लेने के अधिकार और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उद्यमिता विकास के अंतर्गत महिलाओं को विपणन की आधुनिक तकनीकों और उत्पाद पैकेजिंग से भी परिचित कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेलों, प्रदर्शनियों और विशेष बिक्री केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे ग्रामीण उत्पादों का उचित मूल्य सीधे महिला उत्पादकों को मिल रहा है। आर्थिक स्वावलंबन ने बलरामपुर की महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामूहिकता की भावना का विकास किया है। अब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे पारिवारिक एवं सामुदायिक विषयों पर सक्रिय होकर निर्णय ले रही हैं। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत न होकर पूरे ग्रामीण परिवेश को सकारात्मक दिशा दे रहा है। बलरामपुर जनपद में क्रियान्वित किए जा रहे आजीविका संवर्धन मॉडल से यह स्पष्ट है कि लक्षित वित्तीय सहयोग, संस्थागत मार्गदर्शन और महिलाओं की लगन से किसी भी पिछड़े क्षेत्र का कायाकल्प संभव है। समूह से जुड़ी महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की मूक लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण विकास की कुशल संचालक बन चुकी हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साझा विजन से संचालित यह अभियान ग्रामीण अंचल से गरीबी उन्मूलन और महिला नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिला प्रशासन के सतत प्रयासों से जनपद बलरामपुर की 'लखपति दीदियां' आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर साकार करने में सहायक हो रही हैं।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

आवारापन 2' का जलवा बरकरार! दुनियाभर में 150 करोड़ का आंकड़ा पार

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने कई अन्य बड़ी फिल्मों से टक्कर के बावजूद शानदार कमाई की है। फिल्म ने महज कुछ ही दिनों में दुनियाभर में 150 करोड़ से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने घरेलू और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 'आवारापन 2' ने अब तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 161.67 करोड़ की कमाई की है, जिसमें विदेशी बाज़ारों से हुई 26.30 करोड़ की कमाई भी शामिल है। घरेलू कलेक्शन की बात करें तो, 'आवारापन 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पहले सोमवार को गिरावट देखी गई। ओपनिंग वीकेंड के दौरान डबल डिजिट में कमाई करने वाली इस फिल्म ने चौथे दिन 9.25 करोड़ कमाए। पांचवें दिन इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इसने 9.75 करोड़ कमाए, लेकिन छठे दिन यह गिरकर 6.75 करोड़ पर आ गई। सातवें दिन फिल्म ने भारत में 6 करोड़ कमाए। इसके साथ ही, फिल्म का कुल इंडिया कलेक्शन 113.50 करोड़ हो गया है। फिल्म ने हिंदी भाषा में खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी कुल ऑक्यूपेंसी 15.25% रही और गुरुवार, 20 अगस्त को नाइट शो में यह 20.08% तक पहुंच गई। दुनिया भर में कलेक्शन के ?150 करोड़ पार करने के साथ, 'आवारापन 2' इस महीने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से हुआ। गौरतलब है कि 'आवारापन 2' ने इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी सोलो ओपनिंग दर्ज की है। फिल्म ने रिलीज़ के तीन दिनों के भीतर ही दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और पांच दिनों के भीतर भारत में भी 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली। नितिन कक्कड़ की डायरेक्ट की गई 'आवारापन 2', 2007 की फ़िल्म 'आवारापन' का सीक्वल है, जिसे समय के साथ काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। इस सीक्वल में इमरान हाशमी 'शिवम पंडित' के रोल में वापसी कर रहे हैं। इसमें दिशा पाटनी फीमेल लीड रोल में हैं और शबाना आज़मी विलेन का किरदार निभा रही हैं। फ़िल्म में विजयंत कोहली, पूरन गब्बी और सुविंदर विक्की भी अहम भूमिकाओं

शर्मिला टैगोर से कंगना बोलीं- हिंदू-मुस्लिम सोच से बाहर आइए

एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की वंदे मातरम पर टिप्पणी के बाद कंगना रनोट ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर कहा कि हिंदू-मुस्लिम सोच से बाहर आइए। एक कलाकार के तौर पर मैं हैरान हूं कि कला और कविता को लेकर उनकी सोच इतनी छोटी और बनावटी कैसे हो सकती है। शर्मिला टैगोर ने कहा था कि वंदे मातरम के कुछ हिस्से एक ईश्वर को मानने वाले लोगों की आस्था से मेल नहीं खा सकते। गीत में कई देवताओं का जिक्र है। इस गीत के दो अंतरे ही अच्छे हैं। कंगना ने शर्मिला टैगोर के इंटरव्यू का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'मैं खुश हूं कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्ति के बारे में बात की। किसी भी कविता या गीत में शब्द रूपक होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए हर तरह की कल्पना करता है और असंभव लगने वाली समानताएं खींचता है। विवेकानंद ने कहा था कि मुझे ऐसे युवा चाहिए, जो लोहे जैसे बने हों, जिनकी हड्डियां फौलाद की हों और जिनकी नसों में बिजली दौड़ती हो। विवेकानंद मौसम का अनुमान नहीं बता रहे थे। वह केवल शक्ति को जगाने की मांग कर रहे थे। कृपया हिंदू-मुस्लिम सोच से बाहर आइए। भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों, डॉक्टर भी ताकत को शक्ति कहते हैं। आइए, एक-दूसरे को अपनों की तरह अपनाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और उस जोरदार तरीके से गले मिलने से भी मुझे परेशानी नहीं है, जैसे आप हमेशा मिलती हैं।' शर्मिला टैगोर ने न्यूज एजेंसी IANS के साथ बातचीत में कहा, 'बहुत से धार्मिक लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, कई ईश्वरों में नहीं। वंदे मातरम में एक अंतरा है, जिसमें कई देवताओं का जिक्र है। जो लोग एक धर्म, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके लिए 'वंदे काली, वंदे दुर्गा' कहना मुश्किल है। अगर हम भारत के सभी धार्मिक लोगों को साथ लेकर चलें तो वंदे मातरम पहले दो अंतरे बहुत अच्छे हैं।' हालांकि, शर्मिला टैगोर ने अब तक कंगना के कमेंट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

श्वेता तिवारी ने ऑनलाइन बदसलूकी करने वाले ट्रोल्स पर निकाला गुस्सा, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से पूछे तीखे

मशहूर टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली ऑनलाइन बदसलूकी और अभद्र भाषा के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठाई है। इंस्टाग्राम पर साझा की गई पोस्ट्स की एक श्रृंखला में 45 वर्षीय अभिनेत्री ने ट्रोल्स की मानसिकता और समाज के दोहरे मापदंडों पर करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने एक मराठी ट्रोलर का पर्दाफाश करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से भी सवाल दागे।इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट में, एक्ट्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले ट्रोलर्स की आलोचना की और कहा कि उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि ऐसी बातें करने वाले कुछ लोग अच्छे परिवारों से आते हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या ऐसा व्यवहार 'मराठी मानूस' (मराठी व्यक्ति) के गौरव और सम्मान के अनुरूप है। तिवारी ने उस ट्रोलर की इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसने कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की थी। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति डॉक्टर है और उसकी प्रोफ़ाइल पर उसकी पत्नी और बच्चे की तस्वीरें हैं। 45 वर्षीय एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए अपनी पोस्ट शुरू की। उन्होंने कहा कि यह बदसलूकी किसी खास उम्र, पेशे या बैकग्राउंड तक सीमित नहीं है। उन्होंने लिखा, 'आज मैं एक ऐसी बात पर बात करना चाहती हूं जो बहुत चिंताजनक है और दुर्भाग्य से सोशल मीडिया पर बहुत आम है: किसी महिला को 'र****' (अपमानजनक शब्द) कहना। कोई भी महिला। किसी भी उम्र की। किसी भी पेशे की। किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी पुरुष ऑनलाइन आकर किसी महिला को 'र****' कह सकता है। ' एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग पढ़े-लिखे हैं और ऐसे परिवारों से आते हैं जहां महिलाएं उनके जीवन का अहम हिस्सा हैं। तिवारी ने आगे कहा, 'और मुझे हैरानी इस बात से होती है कि ये पुरुष ज़रूरी नहीं कि अनपढ़ हों या मुश्किल बैकग्राउंड से हों। उनमें से कई पढ़े-लिखे हैं, अच्छे परिवारों से आते हैं, उनकी पत्नियां, बेटियां, मां और बहनें हैं... और फिर भी वे किसी दूसरी महिला के लिए सबसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने में पूरी तरह सहज महसूस करते हैं। ' इसके बाद उन्होंने एक इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, 'मैंने एक प्रोफ़ाइल खोली। वह व्यक्ति डॉक्टर है।

उसकी प्रोफ़ाइल पर उसकी पत्नी और बच्चे की खूबसूरत तस्वीरें हैं। एक और पोस्ट में, तिवारी ने सवाल किया कि कोई व्यक्ति अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करते हुए किसी दूसरी महिला के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है। उन्होंने लिखा, 'और मैंने सोचा कि किसी दूसरी महिला से इस तरह बात करने के बाद आप उस परिवार में कैसे जाते हैं? ज़ाहिर है, वह राज ठाकरे या उनकी पार्टी का समर्थक भी है।' इसके बाद तिवारी ने महाराष्ट्र और मराठी संस्कृति से अपने जुड़ाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी महाराष्ट्र में रही हैं और मुंबई में ही पैदा हुई और पली-बढ़ी हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं अपनी पूरी ज़िंदगी महाराष्ट्र में रही हूँ। मेरे पिता मुंबई में पले-बढ़े। मैं मुंबई में पैदा हुई और पली-बढ़ी। मैंने हमेशा 'मराठी माणूस' होने के गर्व और सम्मान को महसूस किया है। ' उन्होंने याद किया कि कैसे मराठी महिलाएँ गर्व से खुद को 'मराठी मुलगी' कहती थीं और कहा कि वह यह मानते हुए बड़ी हुई हैं कि मराठी संस्कृति महिलाओं की ताकत और सम्मान का आदर करती है। फिर तिवारी ने सीधे सवाल किया कि क्या जो लोग खुद को 'मराठी माणूस' कहते हैं, उन्हें ऑनलाइन महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? उन्होंने लिखा, 'जब मैं देखती हूँ कि जो लोग गर्व से खुद को 'मराठी माणूस' कहते हैं, वे महिलाओं के डीएम में आकर उन्हें 'र****' (गाली) कहते हैं, तो मुझे सच में पूछना पड़ता है: क्या 'मराठी माणूस' होने का मतलब यही रह गया है? '

राज ठाकरे से मुखातिब होते हुए उन्होंने आगे कहा, 'राज ठाकरे, अगर ऐसे लोग आपके समर्थक हैं, तो मैं सच में जानना चाहूँगी... क्या आपको लगता है कि यह सही व्यवहार है? 'तिवारी ने आगे कहा कि मराठी होने की पहचान या महाराष्ट्र के प्रति प्यार दिखाने में महिलाओं का सम्मान करना भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने लिखा, 'क्योंकि मराठी बोलना, खुद को 'मराठी माणूस' कहना या महाराष्ट्र से प्यार का दावा करना ही काफी नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना भी उस पहचान का हिस्सा है। 'उन्होंने अपनी पोस्ट का समापन यह पूछते हुए किया कि क्या जो पुरुष ऑनलाइन महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, वे अपनी ही परिवार की महिलाओं के लिए ऐसी भाषा को स्वीकार करेंगे? तिवारी ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान खुद को और दूसरे कंटेस्टेंट्स को झेलनी पड़ी बदसलूकी के बारे में भी बात की। 'द ट्रेटर्स 2' की अपनी साथी कंटेस्टेंट पारुल गुलाटी को टैग करते हुए, उन्होंने उस इंस्टाग्राम लाइव को याद किया जो एक्ट्रेस ने शो के कंटेस्टेंट्स के साथ किया था। तिवारी ने लिखा, 'कल ही, @gulati06 ने 'द ट्रेटर्स' के कंटेस्टेंट्स के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव शुरू किया। मैं कमेंट्स देख रही थी, और मैंने देखा कि बहुत से लोग हमें आसानी से 'र****' कह रहे थे। मुझे सच में समझ नहीं आता कि यह कैसे सामान्य हो गया है। ' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ऑनलाइन कमेंट्स में उनके बच्चों को निशाना बनाया गया था।

उन्होंने कहा, 'कभी-कभी लोग मेरे, मेरे आठ साल के बेटे और मेरी बेटी के बारे में बहुत ही परेशान करने वाली बातें करते हैं। और जब मैं उनकी प्रोफ़ाइल खोलती हूँ, तो मुझे उनकी पत्नियों, बेटियों और परिवारों की तस्वीरें दिखती हैं। 'ऐसे व्यवहार के पीछे दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए तिवारी ने आगे कहा, 'साफ़ है कि उनकी ज़िंदगी में भी महिलाएँ हैं, जिनकी गरिमा पर किसी और का हमला उन्हें कभी मंजूर नहीं होगा। तो फिर किसी ऐसी महिला का अनादर करना कैसे सही हो सकता है, जिसका आपसे कोई लेना-देना ही नहीं है? '

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद श्री सज्जन कुमार के निधन पर गहरा शोक

दिल्ली की राजनीति के वरिष्ठ एवं जनप्रिय कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद श्री सज्जन कुमार जी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकेठ निधन के समाचार से दिल्ली सहित पूरे देश के राजनीतिक, सामाजिक एवं जनसेवा से जुड़े क्षेत्रों में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा उनके शुभचिंतकों ने इसे सार्वजनिक जीवन की एक अपूरणीय क्षति बताया है। श्री सज्जन कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1977 में निगम पार्षद के रूप में की थी। अपने अथक परिश्रम, जनसंपर्क और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के बल पर उन्होंने शीघ्र ही दिल्ली की राजनीति में एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर ली। इसके बाद वे कई बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और सांसद के रूप में

दिल्ली तथा देश की जनता की सेवा करते रहे।

अपने लंबे राजनीतिक जीवन में श्री सज्जन कुमार ने हमेशा आम लोगों के सुख-दुःख में सहभागी बनकर कार्य किया। वे एक मृदुभाषी, मिलनसार, सहज एवं जन-जन में लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके निवास एवं कार्यालय के द्वार सदैव आम जनता के लिए खुले रहते थे और वे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। यही कारण था कि वे केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए विश्वास और अपनत्व का प्रतीक बन गए थे।

दिल्ली के विकास, जनकल्याण एवं संगठन को मजबूत बनाने में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सशक्त नेताओं में उनकी गिनती होती थी और उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से कांग्रेस परिवार ने एक अनुभवी, लोकप्रिय एवं समर्पित नेता को खो दिया है।

एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (पंजीकृत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्र टाइम्स के संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने श्री सज्जन कुमार जी के निधन पर गहरा दुःख एवं शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री सज्जन कुमार जी का जीवन जनसेवा, संघर्ष और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। वे हमेशा पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते थे और सभी वर्गों में समान रूप से सम्मानित थे।

श्री चतुर्वेदी ने कहा कि दिल्ली की राजनीति में श्री सज्जन कुमार का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उनका सरल स्वभाव, मधुर वाणी, जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता तथा लोगों के प्रति आत्मीयता उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान प्रदान करती थी। उनके निधन से जो रिक्तता उत्पन्न हुई है, उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है।

उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बदले न्यायिक सेवा में प्रवेश के नियम, अब एक साल वकालत कर भी बन सकेंगे जज

नई दिल्ली । न्यायिक सेवा में प्रवेश से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की प्रैक्टिस को अनिवार्य शर्त बनाए रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने बार में जरूरी प्रैक्टिस की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक और शर्त लगाई है। इसके तहत न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को एक साल का गहन प्रशिक्षण राज्य न्यायिक अकादमी में लेना होगा। इसके बाद छह महीने जिला न्यायाधीश/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के साथ क्लर्कशिप और छह महीने किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज के साथ क्लर्कशिप करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण अवधि के संबंध में भी महत्वपूर्ण छूट दी है, जो 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। अदालत ने कहा, ''निर्देश यह है कि तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता के बावजूद सभी कानून स्नातक आवेदन करने के पात्र होंगे। इस तथ्य को देखते हुए कि समीक्षा के तहत फैसले को सुनाए जाने के बाद एक साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एक साल की सक्रिय प्रैक्टिस पूरी कर लेने वाला माना जाएगा और उन्हें इस अवधि के लिए प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी।''सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खुली अदालत में उन समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिनमें न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम तीन साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य करने वाले उसके फैसले को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने कहा था कि तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के लिए एक खाली अवधि पैदा करती है। इससे प्रतिभाशाली उम्मीदवार कानून की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद न्यायिक सेवा को करियर के विकल्प के रूप में चुनने से हतोत्साहित हो सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ''इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें युवा प्रतिभाओं पर इसके प्रभाव को भी देखना होगा। हम इसे इस तरह कैसे लागू करें कि इससे प्रतिभाशाली उम्मीदवार वंचित न हों? आज कानून की पढ़ाई पूरी करने वाला नया स्नातक पात्र नहीं है।'' महिला उम्मीदवारों के सामने आने वाली सामाजिक परिस्थितियों को लेकर भी सीजेआई ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस शर्त का असर महिला न्यायिक अधिकारियों की तैयारी कर रही उम्मीदवारों पर ज्यादा पड़ सकता है। उन्होंने कहा, ''लड़कियां वास्तव में परेशान हैं।

लड़कियां हमारी प्रतिभा की क्षमता हैं।'' उन्होंने कहा कि परिवार और समाज के दबाव, शादी और स्थान बदलने जैसी परिस्थितियों के कारण कई महिलाएं जरूरी वर्षों की प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाएं, ऐसी आशंका है। समीक्षा याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिए वकील के तौर पर कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस को अनिवार्य किया गया था। उस फैसले में 2002 से पहले की व्यवस्था को बहाल किया गया था। कोर्ट ने माना था कि ट्रायल कोर्ट के जजों में क्षमता और परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में पहले का अनुभव जरूरी है। एक समीक्षा याचिका में कहा गया कि फैसले में शेट्टी आयोग की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को नजरअंदाज किया गया। आयोग ने अनिवार्य प्रैक्टिस की शर्त हटाने की सिफारिश की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि कानून की पढ़ाई के पाठ्यक्रम में अदालतों के दौरे और इंटर्नशिप पहले से शामिल हैं। इसके अलावा, न्यायिक अधिकारी पद संभालने से पहले तय प्रशिक्षण से गुजरते हैं। ऐसे में तीन साल की मुकदमेबाजी की अनिवार्यता जरूरी नहीं है।

दिल्ली में दो करोड़ की चोरी: कार में रखे गहने-हीरे से भरे तीन बैग उड़ाए, जयपुर के ज्वेलर को निशाना बनाया

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके से एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां एक कार की पिछली खिड़की तोड़कर लगभग दो करोड़ रुपये के गहने और हीरे ले जाए गए। यह वारदात 19 अगस्त को बीकानेर चौक के पास हुई। घटना की सूचना मिलते ही करोल बाग थाना पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर क्राइम टीम, स्पेशल स्टाफ व एएटीएस की टीमों के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि 19 अगस्त को बीकानेर चौक के पास खड़ी एक कार की पिछली खिड़की तोड़कर तीन बैग चोरी करने की जानकारी मिली थी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई। शिकायतकर्ता जयपुर का एक ज्वेलर बताया जा रहा है, जो अपने कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ था। उसके अनुसार, चोरी हुए बैगों में गहने और हीरे रखे थे, जिनकी कुल कीमत लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई है।

अशोका एक्सप्रेस

अशोका एक्सप्रेस की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र

प्रिय पाठक, विज्ञापन दात्ता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।

संपादक: विजय कुमार

Website: https://ashokaexpress.com/, Email:-ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810674206

अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते है।

Account Holder Name : ASHOKA EXPRESS
Bank Account No. : 10650995502 & 41856402452
IFSC Code : SBIN0004846
UPI ID : 9810674206@sbi

ई20 नीति की तत्काल समीक्षा हो और जनता को बिना इथेनॉल वाला विकल्प मिलेः कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र की ई20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) नीति की तत्काल समीक्षा करने तथा उपभोक्ताओं को बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति के कारण जनता को ''महंगे खाने और महंगे सफर'' दोनों की कीमत चुकानी पड़ रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ''गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी, ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं हो सकती।'' रमेश ने दावा किया कि एथेनॉल उत्पादन में गन्ने और अनाज के इस्तेमाल के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 25 लाख टन चीनी-लायक गन्ना एथेनॉल उत्पादन में चला गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमत 48 रुपये से बढ़कर 67 रुपये

प्रति किलोग्राम और गुड़ की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। उन्होंने दावा किया कि चावल और मक्के का आटा भी क्रमशः 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत महंगा हुआ है, जबकि पशु आहार की कीमत में 10.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस महासचिव ने ई20 के कारण वाहनों के माइलेज और उनकी अनुकूलता को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'जो वाहन 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें खराबी का जोखिम हो सकता है और बिना समुचित परीक्षण के वाहनों में माइलेज कम होने की आशंका है।' रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए पेट्रोल के विकल्प सीमित कर दिए हैं, जबकि ई20 को लेकर वाहन मालिकों के बीच माइलेज और अनुकूलता संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं। उन्होंने यह सवाल भी किया कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी और पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाए जाने से लागत में आने वाली कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की गई? रमेश ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ई20 नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कार्य समिति ने 19 अगस्त को ई20 के कारण कम माइलेज, वाहनों की अनुकूलता, उपभोक्ताओं के सीमित विकल्प और पर्यावरणीय क्षति से जुड़े सवालों पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, 'हमारी मांग है कि ई20 नीति की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए और जनता को बिना इथेनॉल वाले विकल्प मिलने चाहिए। गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी, ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं हो सकती।'

संसद मार्ग पर राहुल गांधी का धरना, बीजेपी ने 'अराजक राजनीति' का लगाया आरोप

नई दिल्ली।

बीजेपी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में धरना देकर 'अराजक राजनीति' करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि उन्हें कानून-व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है और वे 'तुष्टिकरण की राजनीति' कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी की यह टिप्पणी तब आई जब गांधी ने पुलिस स्टेशन में धरना दिया। वे 20 जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए एक युवक के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ 'बर्बरता' एक 'गंभीर अपराध' है। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि गांधी ध्यान भटकाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को एहसास हो गया था कि वंदे मातरम मुद्दे पर उनका रुख गलत था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मुझे शक है और मेरा आरोप है कि कांग्रेस वंदे मातरम पर अपने रुख को लेकर फंस गई है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।' प्रसाद ने कहा कि गांधी ने बिना अनुमति या पूर्व सूचना के धरना दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पहले से ही चल रही है और उन्होंने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन करने के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि मामले की जांच हो रही थी। प्रसाद ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष भी है। प्रसाद ने कहा, 'कांग्रेस राहुल गांधी की तुष्टिकरण की राजनीति से चलने वाली पार्टी बन गई है।' गांधी के साथ 19 वर्षीय युवक साहिल लोचब भी था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि स्वतःदर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि 'ऊपर से आदेश हैं'। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे न्याय से डरते हैं।

दिल्ली में एच1एन1 का बढ़ा प्रकोप, एक दिन में मिले 114 नए मरीज; 2026 में आंकड़ा 1777 तक पहुंचा

नई दिल्ली। दिल्ली में एच1एन1 संक्रमण की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। 20 अगस्त को राजधानी में एक ही दिन में 114 नए एच1एन1 मरीज मिले। इसके साथ ही वर्ष 2026 में अब तक पुष्ट मरीजों की संख्या बढ़कर 1,777 हो गई है। दो सप्ताह पहले छह अगस्त तक यह संख्या 1,344 थी। यानी महज 14 दिन में 433 नए मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में 229 मामले थे, ऐसे में इस वर्ष अब तक मामले करीब आठ गुना हो चुके हैं। 20 अगस्त को दिल्ली में कुल 159 इन्फ्लुएंजा मरीज मिले, जिनमें 114 एच1एन1 के थे। यानी एक दिन में सामने आए इन्फ्लुएंजा मामलों में बड़ी हिस्सेदारी एच1एन1 की रही। अगस्त में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में संक्रमण की स्थिति और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। छह अगस्त तक दिल्ली में 1,344 एच1एन1 मामले सामने आए थे। तब भी यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि के 229 मामलों से करीब छह गुना था। अब 20 अगस्त तक संख्या 1,777 पहुंच गई है। यानी अगस्त के शुरुआती 20 दिनों में ही बड़ी संख्या में नए मामले जुड़े हैं।

एम्स के विशेषज्ञों ने भी मानसून और तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच इन्फ्लुएंजा मरीजों में बढ़ोतरी की बात कही है। एम्स की ओपीडी में फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीज बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बुजुर्गों और पहले से फेफड़े, हृदय, मधुमेह तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों में संक्रमण गंभीर हो सकता है। हर बुखार मरीज की नहीं हो रही जांच बढ़ते मामलों के बीच हर बुखार मरीज की एच1एन1 जांच नहीं की जा रही है। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बुखार के मरीजों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। सामान्य लक्षण वाले ए और बी श्रेणी के मरीजों की सामान्य तौर पर जांच नहीं होती, जबकि गंभीर लक्षण वाले सी श्रेणी के मरीजों के सैंपल आरटी-पीसीआर जांच के लिए भेजे जाते हैं। लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डा. बीएल चौधरी ने कहा कि हर मरीज की जांच नहीं हो रही है। जिन मरीजों में लक्षण देखकर इन्फ्लुएंजा वायरस की संभावना लगती है, उन्हीं के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इस सीजन अब तक कुल कितने मरीजों की एच1एन1 जांच हुई, इसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट पर भी कुल जांच का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। गंभीर मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट समय से नहीं मिलने की शिकायतें भी मरीजों और स्वजन की ओर से सामने आ रही हैं।

एक्शन मोड में दिल्ली नगर निगमः 75 किमी रेलवे ट्रैक पर एंटी-लार्वा स्प्रे, मच्छरों के खिलाफ मेगा अभियान

नई दिल्ली। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को महापौर प्रवेश वाही ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 'मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन-2026' (एमटीटी-2026) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निगम और उत्तर रेलवे के संयुक्त अभियान के तहत पहले चरण में करीब 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और उसके आसपास के क्षेत्रों में एंटी-लार्वल दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। महापौर ने कहा कि बारिश के दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे निचले इलाकों और अन्य स्थानों पर पानी जमा होने से मच्छरों के प्रजनन की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन चक्र को शुरुआती स्तर पर ही रोकना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ दिल्ली ही स्वस्थ दिल्ली की मजबूत नींव है। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वच्छता, जलभराव रोकने और मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को समय रहते खत्म करना जरूरी है।

पावर स्प्रे टैंकर ट्रेन के साथ चलेंगे

वहीं, अभियान से पहले निगम ने रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर संभावित मच्छर प्रजनन स्थलों की पहचान की। अब चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में एंटी-लार्वल दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए पावर स्प्रे टैंकर ट्रेन के साथ चलेंगे, जिससे उन स्थानों पर भी दवा पहुंचाई जा सकेगी जहां सामान्य तरीके से पहुंचना मुश्किल है।

सितंबर तक चलेगा अभियान

इस अभियान के तहत नई दिल्ली से राठधाना, आदर्श नगर-बादली, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली शाहदरा, हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, सफदरजंग, किशनगंज, सदर बाजार, दिल्ली कैंट, पालम-गुड़गांव, फरीदाबाद और ओखला-तुगलकाबाद समेत विभिन्न रेलवे मार्गों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। यह अभियान सितंबर तक चलेगा। अभियान की निगरानी संबंधित जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों, सहायक मलेरिया अधिकारियों, मलेरिया अधीक्षकों और एपिडेमियोलॉजिस्ट द्वारा की जाएगी। प्रत्येक ट्रिप के लिए पावर स्प्रे टैंकर, चालक, पानी और आवश्यक इंसैक्टिसाइड व लार्विसाइड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। निगम और उत्तर रेलवे की टीमें समन्वय के साथ अभियान को आगे बढ़ाएंगी। महापौर ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को केवल निगम की जिम्मेदारी न समझें। घरों और आसपास पानी जमा न होने दें तथा कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें।

रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति, दिल्ली पुलिस ने पहले एनओसी देने से किया था इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पदाधिकारियों को शुक्रवार 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। हालांकि, इस आंदोलन को पहले अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इंकार कर दिया था। हालांकि, सोशल मीडिया में इस बात का विरोध जताया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति देने में काफी देरी की गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से एक्स पर सूचना दी गई है कि 21 अगस्त को रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एनओसी जारी कर दिया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, दरिया गंज के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, हर्ष दुबे और अभिषेक अग्निहोत्री (रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट) को रामलीला ग्राउंड में अधिकतम 500 लोगों तक सीमित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। पुलिस की अनुमति के अनुसार, यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक ही आयोजित किया जा सकेगा। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जुलूस या ठहराव की अनुमति नहीं है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इनका उल्लंघन होने पर एनओसी किसी भी समय रद की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस सार्वजनिक सूचना को साझा करते हुए सभी से कानून का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने संबंधित कमला मार्केट थाना के माध्यम से यह पत्र भेजा है और इसकी प्रति एसीपी कमला मार्केट तथा संबंधित थाने को भी दी गई है।

बीजेपी ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है और जिम्मेदारी से भाग रही हैः कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ''ध्रुवीकरण'' का प्रयास करने, जिम्मेदारी से भागने और गैर जरूरी मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए इसे ''असंवैधानिक'' करार दिया और कहा कि जब तक 'पैलेट गन से घायल' युवक साहिल लोचब के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस नेता संसद मार्ग स्थित थाने से नहीं हटेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि भाजपा जिम्मेदार से भागने के लिए गैर-जरूरी मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने के परिसर में धरने पर बैठे हैं। संसद मार्ग थाना परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में रमेश ने कहा कि कांग्रेस की मांग

''बहुत सरल'' है कि प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसका नंबर दिया जाए। उन्होंने कहा, ''साहिल ने वास्तविक मांग की है कि प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मांग को आवाज दे रहे हैं। साहिल ने पुलिस द्वारा पैलेट गन के कथित अवैध इस्तेमाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।'' रमेश ने कहा कि राहुल गांधी स्पष्ट हैं कि जब तक नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती, वे यहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, ''जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। हम जो कर रहे हैं, वह संविधान के अनुरूप है।'' कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा की ओर से ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया है जो असंवैधानिक है।

इससे पहले, राहुल गांधी साहिल लोचब के साथ मंदिर मार्ग थाने पहुंचे थे और कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के कारण घायल हुए लोचब के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे संसद मार्ग थाने पहुंचे और डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात की जिसके बाद वह वहां धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान लोचब की आंखों और पेट में पैलेट (छर्रे) लगे थे और बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेंटर में उनकी सर्जरी हुई थी। रमेश ने कहा, 'स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर लीक से परेशान एक भारतीय युवा 20 जुलाई को विरोध-प्रदर्शन कर रहा था।

रक्षाबंधन पर देश में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है व्यापार, उद्योग जगत का क्या अनुमान

मुंबई । रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उत्पादों के प्रति बढ़ते विश्वास और राष्ट्रभावना का भी उत्सव बन गया है। देशभर के बाजारों में स्वदेशी राखियों की अच्छी मांग देखी जा रही है और विभिन्न राज्यों में तैयार की गई विशिष्ट भारतीय राखियां उपभोक्ताओं का विशेष आकर्षण बनी हुई हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने कहा कि इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर देशभर में लगभग 25 हज़ार करोड़ रुपये का व्यापार का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत अधिक है जबकि उपहार, मिठाई, वस्त्र एवं अन्य त्योहारी उत्पादों को मिलाकर कुल व्यापार 30 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच सकता है।पिछले वर्ष राखी का व्यापार देश भर में लगभग 17 हज़ार रुपए का हुआ था वहीं वर्ष 2023 में यह व्यापार 12 हज़ार करोड़ रुपये का हुआ था। कैट के अनुसार देशभर के बाजारों में इस वर्ष भी चीनी राखियों की कोई मांग नहीं है। व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं ने पूरी तरह स्वदेशी राखियों को अपनाया है और बाजारों में केवल भारतीय निर्मित राखियां ही उपलब्ध हैं। कैट देश के विभिन्न शहरों में विशेष स्वदेशी मेले आयोजित करने जा रहा हैं, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित राखियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री की जाएगी। कैट का मानना है कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति बढ़ते रुझान और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के कारण भारतीय कारीगरों, महिला उद्यमियों, लघु उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों को इस रक्षाबंधन पर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। धारावी के राखी कारोबारी हरमुख लाल पटवा ने बताया कि बाजार में कोलकाता और दिल्ली से भी राखियां

आई हैं। ग्राहकों की पसंद में भी बदलाव दिख रहा है। खासकर बच्चों के लिए लाइट वाली राखियों की मांग बनी हुई है। इनमें चीन से आने वाले आइटम की हिस्सेदारी भी है। पटवा पिछले करीब 25 दिनों से राखी की दुकान लगाए हुए हैं। राखी का सीजन खत्म होने के बाद वे इमिटेशन ज्वेलरी के कारोबार में लौट जाएंगे। राखी उत्पादक गंगादीन पटवा के मुताबिक राखी का कारोबार सीमित समय के लिए होता है। इसलिए उत्पादन और स्टॉक का आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मांग से ज्यादा राखियां तैयार हो जाएं तो उन्हें अगले साल तक संभालकर रखना मुश्किल होता है।

इस दौरान डिजाइन और ट्रेंड बदल जाने से पुराना स्टॉक बिकना भी मुश्किल हो जाता है और बचा हुआ माल उस साल की कमाई को नुकसान में बदल सकता है। उन्होंने बताया कि चीन से भी बड़ी मात्रा में राखियां बाजार में आ रही हैं और लाइट वाली राखियां बच्चों में लोकप्रिय हो रही हैं। चार रुपये से लेकर बाजार में सौ रुपए तक की राखियों की मांग बनी हुयी है। राखी व्यापारी मंगल जैन ने कहा कि राखी बनाने की लागत लगातार बढ़ी है। कारीगरों की मजदूरी भी बढ़ी है। अक्सर तीन-चार साल के अंतराल पर उत्पादन मांग से अधिक हो जाता है और व्यापारियों के पास स्टॉक बच जाता है। अगले साल तक उस स्टॉक को संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि तब तक डिजाइन और ट्रेंड बदल चुके होते हैं।

इसलिए राखी के कारोबार में बाजार की मांग को समझकर स्टॉक रखना सबसे जरूरी है। ज्वेलरी मेकर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शाह ने बताया कि सोने-चांदी ने निवेश के तौर पर अच्छा रिटर्न दिया है। इसके चलते त्योहार पर कुछ ग्राहक सोने-चांदी की हल्की राखियां भी पसंद कर रहे हैं। इन राखियों के लिए पहले से ऑर्डर देकर निर्माण कराया जा रहा है। खास बात यह है कि हल्की राखियों को ग्राहक बाद में आभूषण की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबारियों का कहना है कि रक्षाबंधन से पहले अंतिम दिनों में राखी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इस बार त्योहार महीने के अंत में होने के कारण ग्राहकों के बजट पर दबाव रह सकता है परन्तु भावनात्मक त्यौहार के लिए लोग बजट नहीं देखते इससे व्यापारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है।

प्रसादपुर में विधिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीणों को अधिकारों व योजनाओं की दी जानकारी

कुशीनगर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन (महिला कल्याण विभाग) के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को ग्राम पंचायत प्रसादपुर में विधिक जागरूकता सह जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज भुवन ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव/अपर जिला जज ने ग्रामीणों को विधिक अधिकारों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के डिस्ट्रिक्ट मिशन कोआर्डिनेटर नलिन सिंह ने निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना एवं पारिवारिक लाभ योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की पात्रता और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने पात्र लोगों से योजनाओं का लाभ लेने तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को भी लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की। वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर रीता यादव ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090, वन स्टॉप सेंटर/महिला हेल्पलाइन 181, 112, 108 एवं 102 के उपयोग और महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या परेशानी की स्थिति में महिलाएं 181 पर अपनी समस्या साझा कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से हिंसा को सहन न करने और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध सहायता सेवाओं का उपयोग करने की अपील की।

कार्यक्रम में ग्राम प्रधान पंकज गुप्ता, पंचायत सहायक प्रवीण, सामाजिक कार्यकर्ता रामवृक्ष गिरि, पीएलवी डिम्पल उपाध्याय एवं अभिमन्यु सिंह सहित ग्राम पंचायत के सैकड़ों महिला-पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को विधिक अधिकारों, महिला एवं बाल सुरक्षा, सरकारी योजनाओं तथा उपलब्ध सहायता एवं हेल्पलाइन सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया।

सड़क की खुदाई कराकर परखी गुणवत्ता, डीएम के औचक निरीक्षण से कार्यदायी संस्थाओं में हड़कंप

देवरिया।

जनपद में जारी विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता और मानकों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने दो प्रमुख निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पिपरा चंद्रभान से सहजौली मार्ग की गुणवत्ता जांचने के लिए मौके पर ही सड़क की खुदाई कराई गई और उसकी विभिन्न परतों का परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत 6.20 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 6.92 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निरीक्षण के दौरान तकनीकी टीम ने पाया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप है। इसके बाद जिलाधिकारी भलुअनी विकासखंड परिसर पहुंचे, जहां 2.58 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन आवासीय परियोजना का जायजा लिया गया। कलेक्ट्रेट प्रशासन ने मौके से ईंट, सीमेंट तथा अन्य

2.58 करोड़ की आवासीय परियोजना में प्रयुक्त ईंट व सीमेंट के सैंपल सील

सामग्री के नमूने सील करवाकर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य मार्च 2027 की निर्धारित समयसीमा के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित विभाग व ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मौके पर डीएसटीओ अरुण कुमार सिंह और ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता सूर्य प्रकाश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

तत्काल टिकटों की दलाली का खुलासा, आरपीएफ जांच में बुकिंग कर्मचारी से मिलीभगत का आरोप

बरेली।

तत्काल श्रेणी के रेलवे टिकटों की कथित दलाली के मामले में रेलवे सुरक्षा बल की जांच में अहम खुलासा हुआ है। आरपीएफ पोस्ट बरेली में दर्ज मुकदमा संख्या 649/26, धारा 143 रेलवे एक्ट के तहत चल रही जांच में रविन्द्र कुमार साहू नामक व्यक्ति के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आई जानकारी के आधार पर आरपीएफ ने उसे भी मुकदमे में आरोपी के रूप में संबद्ध किया है।

मुंबई निवासी युवक के बयान से खुली पूरी कहानी

आरपीएफ के मुताबिक रविन्द्र कुमार साहू, पुत्र उमेश कुमार साहू, उम्र करीब 24 वर्ष, मुंबई में रहता है और उसका मूल निवास बिहार के मधुबनी जिले में है। मुकदमे की जांच के सिलसिले में उसे सम्मन भेजा गया था। आरपीएफ पोस्ट बरेली पहुंचने के बाद उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने तत्काल टिकटों की बुकिंग और आगे बेचने से जुड़ी अहम जानकारी दी।

पीतांबरपुर आरक्षण केंद्र के कर्मचारी से मिलीभगत का आरोप

बयान के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को पीतांबरपुर रेलवे आरक्षण केंद्र पर तैनात मुख्य सहायक आरक्षण पर्यवेक्षक शैलेंद्र दुबे के साथ कथित मिलीभगत कर तत्काल श्रेणी के टिकट जारी कराए गए। आरोप है कि इन टिकटों को आगे बुकिंग एजेंट को कमीशन लेकर बेचने की योजना थी।

व्हाट्सऐप संदेश भेजकर कराई गई टिकट बुकिंग

आरपीएफ को दिए बयान के मुताबिक रविन्द्र ने अपने व्हाट्सऐप नंबर से शैलेंद्र दुबे के मोबाइल पर दो व्हाट्सऐप संदेश भेजे थे। इन संदेशों के आधार पर 5 जुलाई 2026 की यात्रा के लिए तत्काल श्रेणी के दो टिकट जारी कराने की बात सामने आई है। आरपीएफ ने जांच में इन डिजिटल

संदेशों और टिकटों को अहम साक्ष्य माना है।

दो तत्काल टिकटों की कुल कीमत 16,340 रुपये

जांच में सामने आए टिकट विवरण के अनुसार दोनों टिकटों की कुल कीमत 16,340 रुपये थी। इनमें एक टिकट 3 AC श्रेणी का था, जिसकी कीमत 11,560 रुपये बताई गई है, जबकि दूसरा स्लीपर श्रेणी का टिकट 4,780 रुपये का था।

एक टिकट का फोटो भेजा, दूसरा पकड़े जाने से पहले रह गया

बयान के मुताबिक एक टिकट जारी होने के बाद उससे संबंधित मूल टिकट का फोटो बुकिंग कर्मचारी द्वारा रविन्द्र को भेज दिया गया था। वहीं दूसरे टिकट के संबंध में आरोप है कि वह टिकट जारी तो कर दिया गया, लेकिन उसका फोटो भेजे जाने से पहले ही आरपीएफ की कार्रवाई में मामला पकड़ में आ गया।

आगरा के बुकिंग एजेंट को टिकट बेचने की बात

आरपीएफ के अनुसार, पूछताछ में रविन्द्र ने बताया कि टिकट आगे किसी आगरा निवासी बुकिंग एजेंट को बेचने के उद्देश्य से जारी कराए गए थे।

यानी जांच में केवल टिकट बनवाने ही नहीं, बल्कि उन्हें आगे कमीशन के बदले बेचने की कथित योजना भी सामने आई है।

आरपीएफ ने साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में जोड़ा

आरपीएफ निरीक्षक मयंक चौधरी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर रविन्द्र कुमार साहू की संलिप्तता धारा 143(1) रेलवे एक्ट के तहत पाई गई। इसके बाद उसे मुकदमा संख्या 649/26 में 20 अगस्त 2026 को रात 8:45 बजे संबद्ध किया गया।

जांच में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका अहम

पूरे मामले में व्हाट्सऐप संदेश, मोबाइल नंबर, टिकट विवरण, PNR और आरक्षण केंद्र से जुड़े रिकॉर्ड जांच के महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। आरपीएफ की जांच से यह भी स्पष्ट करने की कोशिश होगी कि टिकट बुकिंग में कथित मिलीभगत कितने स्तर तक थी और इसमें अन्य लोग या एजेंट भी शामिल थे या नहीं।

आरपीएफ की कार्रवाई से तत्काल टिकटों की दलाली पर सवाल

इस कार्रवाई ने रेलवे आरक्षण केंद्रों से तत्काल टिकटों की बुकिंग और उन्हें कमीशन लेकर आगे बेचने की कथित व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आरपीएफ की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर होने की बात कही गई है।

मिलावटी गुड़ की शिकायतों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, चार प्रतिष्ठानों से नमूने लिए

कुशीनगर। जनपद में मिलावटी गुड़ के निर्माण एवं बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुड़ निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान मिली कमियों पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुधार नोटिस जारी किए गए। मिलावट की आशंका के आधार पर टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से गुड़ एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए। लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान गोडरिया बाजार में अनिरुद्ध गुप्ता के प्रतिष्ठान से गुड़, बसहिया बनबीरपुर में अनुल्लाह के प्रतिष्ठान से गुड़ एवं चीनी, जंगल बनवीरपुर में आशिक रावत के प्रतिष्ठान से गुड़ तथा जरार, जटहा बाजार में नवीन कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान से गुड़ का नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुड़ निर्माण करने वाले कारोबारकर्ताओं को स्वच्छता, हाईजीन एवं खाद्य सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II प्रदीप कुमार राय ने बताया कि जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

19 मुसहर परिवारों के लिए आवासीय परिसर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास

कुशीनगर।

फाजिलनगर विकास खंड के ग्राम सभा बलियवां स्थित मुसहर बस्ती में 19 मुसहर परिवारों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण कार्य का शुक्रवार को देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, क्षेत्रीय विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा एवं ब्लॉक प्रमुख उर्मिला जायसवाल ने भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान चयनित लाभार्थियों को संबंधित भूमि के आवासीय पट्टे के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुसहर परिवारों को आवास एवं

मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आवासीय परिसर में केवल मकानों का निर्माण ही नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, बिजली और पानी सहित बेहतर जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता है। क्षेत्रीय विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों में गरीब एवं वंचित परिवारों को शहरी मॉडल के अनुरूप आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराना है। मुख्य विकास अधिकारी बंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में लगभग 82 डिसमिल भूमि पर आवासीय परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची तैयार होने के बाद योजना के द्वितीय चरण में इसी स्थान से सटे क्षेत्र में अन्य पात्र परिवारों के लिए भी आवासीय परिसर का निर्माण कराया जाएगा।

कार्यक्रम को ब्लॉक प्रमुख उर्मिला जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा, मनोज चौबे, अमिताभ मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास पाण्डेय, विश्वविजय सिंह एवं ग्राम प्रधान संजय यादव ने भी संबोधित किया। संचालन कवि मनंजय तिवारी ने किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक पीयूष सिंह, डीसी मनरेगा राकेश कुमार, एसडीएम कसया विवेक कुमार मिश्रा, तहसीलदार धर्मबीर सिंह, खंड विकास अधिकारी रवि कुमार रंजन सहित संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

जन्माष्टमी, ईद मिलादुन्नबी व रक्षाबंधन को लेकर पीस कमेटी की बैठक

भटनी देवरिया।

थानाध्यक्ष पंकज गुप्ता व नगर चौकी प्रभारी नितिन साहू ने शांति-सौहार्द बनाए रखने की अपील की

आगामी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलादुन्नबी समेत अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर भटनी थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अगुवाई थानाध्यक्ष पंकज गुप्ता एवं नगर चौकी प्रभारी नितिन साहू ने की। बैठक में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों और जुलूसों को लेकर चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने सभी समुदायों के लोगों से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक संदेश प्रसारित नहीं करने की हिदायत दी। थानाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। नगर चौकी प्रभारी नितिन साहू ने लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया।

बैठक में क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

चालान पेंडिंग फिर भी वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू,कार्यप्रणाली पर सवाल

लखनऊ।

परिवहन विभाग में ऑनलाइन और फेसलेस व्यवस्था लागू होने के बावजूद लखनऊ के टीपी नगर आरटीओ कार्यालय में कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। वाहन संख्या यूपी32JB/2179 पर चालान पेंडिंग दिखने के बावजूद वाहन को ट्रांसफर प्रक्रिया में इनवार्ड कर दिया गया। अब मामले में संभागीय निरीक्षक के अनुमोदन की प्रक्रिया बाकी बताई जा रही है। सरकार परिवहन विभाग में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दे रही है। विभाग की 39 सेवाओं को ऑटो अप्रूवल व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसके बावजूद यदि चालान लंबित होने की स्थिति में वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो यह डिजिटल व्यवस्था की निगरानी और आपसी समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े करता है।सवाल यह भी है कि जब वाहन पोर्टल पर चालान लंबित प्रदर्शित हो रहा था तो इनवार्ड करने से पहले इसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या पोर्टल की अलग-अलग व्यवस्थाओं के बीच तकनीकी समन्वय की कमी है या फिर प्रक्रिया में मानवीय स्तर पर चूक हुई?

इसकी जांच से ही स्थिति स्पष्ट होगी।परिवहन विभाग में पारदर्शिता के लिए एटीएस और अन्य डिजिटल व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही हैं। ऐसे में इन व्यवस्थाओं की निगरानी और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।इस मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह से दूरभाष पर संपर्क कर विभाग का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न, 17 में से 14 मामलों का हुआ समाधान

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। समय के साथ व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है और जिन क्षेत्रों में पहले समस्याएं अधिक दिखाई देती थीं, वहां अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण अचानक व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव आता है और जलभराव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले समय में किए गए कार्यों का लाभ स्पष्ट रूप से अब दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी से विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 14 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 3 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। बिलासपुर-तावडू रोड स्थित पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क से आए वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क में 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए बिल्डर द्वारा निर्धारित भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एसोसिएशन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए डेवलपर से आवश्यक भूमि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि बिल्डर/डेवलपर सब-स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त, नियमित एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए सदर बाजार से संबंधित शिकायत में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक का मार्ग सदर बाजार का मुख्य प्रवेश मार्ग होने के साथ-साथ अत्यंत व्यस्त क्षेत्र है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा, ऑटो व अन्य वाहन सड़क पर अव्यवस्थित रूप से खड़े रहते हैं तथा बीच सड़क पर सवारियां बैठाने और उतारने के कारण यातायात प्रभावित होता है। शिकायत के अनुसार इस कारण आम नागरिकों, व्यापारियों तथा आपातकालीन वाहनों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आमजन को सुगम और व्यवस्थित यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड तथा सवारी चढ़ाने-उतारने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाए, ताकि वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े न हों और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। साथ ही, सदर बाजार के मुख्य प्रवेश मार्ग पर नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाए तथा सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखते हुए आमजन के लिए आवागमन सुगम बनाया जाए। झुंड सराय वीरान स्थित कृष्णा कॉलोनी के आरडब्ल्यूए निवासियों ने शिकायत में बताया कि कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित की गई है। कॉलोनाइजरों द्वारा रास्ते की जमीन को बेचने तथा खरीदारों द्वारा उस पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन कर अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को गुमराह कर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने और लोगों की मेहनत की कमाई से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनधिकृत निर्माण एवं कॉलोनी के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रभावित लोगों की समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में लगातार काम किया जाए, ताकि नागरिकों को बार-बार होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान केवल तत्काल राहत तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित विभाग स्थायी समाधान की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त शिकायतों और पूर्व में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी. एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा, सीपी शिवास कविराज, नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त प्रदीप दहिया, डीसी उत्तम सिंह, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर के निगम आयुक्त प्रदीप सिंह, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्बन टैक्सः घटेगा भारत से यूरोप को स्टील और एल्युमिनियम का निर्यात, छोटे उद्योगों को लगेगा झटका

नई दिल्ली । तमाम कूटनीतिक वार्ताओं, मुक्त व्यापार समझौते की मेज पर सौदेबाजी और बाजार खोलने की पेशकशों के बावजूद भारत यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) को टलवाने में नाकाम रहा। यूरोपीय संघ ने साफ कर दिया है कि यह नियम पूरी दुनिया के लिए एक समान है। इसका सीधा मतलब यह है कि जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू होने जा रहे इस टैक्स से अब भारतीय निर्यातकों के लिए बचना नामुमकिन है। भारतीय निर्यातकों को अब यूरोप में अपने माल का प्रवेश कराने के लिए 55 से 80 यूरो प्रति टन तक का अतिरिक्त कार्बन टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिससे यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ेगी। कार्बन टैक्स पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष शुल्क है। यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स शुरुआत में सिर्फ छह प्राथमिक क्षेत्रों स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली पर केंद्रित था। अब इसे इन कच्चे मालों से बनने वाले 180 तैयार उत्पादों (जैसे ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद) तक बढ़ाया जा रहा है। कार्बन टैक्स का सीधा असर भारत के प्रमुख क्षेत्रों आयर एवं स्टील और एल्युमिनियम और उनसे जुड़ी कंपनियों पर पड़ेगा।

औद्योगिक संस्था फिक्की के मुताबिक, भारत से स्टील एवं आयरन और एल्युमियिन का सालाना 6 अरब डॉलर का निर्यात यूरोपीय संघ को होता है। इसमें 3.5 अरब डॉलर का आयरन और 2.5 अरब डॉलर का एल्युमिनियम निर्यात शामिल है। आयरन एवं स्टील क्षेत्र की टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन, जिंदल स्टील और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जैसी बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियां इस टैक्स से सीधे प्रभावित होंगी। आईसीआरआईईआर के अनुमान के मुताबिक, इस टैक्स के कारण यूरोपीय संघ को होने वाले भारतीय स्टील निर्यात में 24 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है।

मामूली बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी, पश्चिम एशिया की चिंताएं बाजार पर हावी

नई दिल्ली । भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन उतार-चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुए। पश्चिम एशिया में बनी अनिश्चितताओं के कारण प्रमुख सूचकांकों की तेजी सीमित रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 3 अंक से अधिक बढ़कर 77,541 के स्तर पर पहुंचा। वहीं, निफ्टी 50 में 20 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और यह 24,252 पर बंद हुआ। बाजार में शुक्रवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहा। हालांकि, अंततः बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ कारोबार समाप्त किया। मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। इस कारण बाजार में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। व्यापक बाजारों ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छी हलचल देखी गई। पावर ग्रिड के शेयरों में 3 फीसदी की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, ट्रेंट के शेयरों में 2 फीसदी की गिरावट आई। भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को अपनी बढ़त को आगे बढ़ाया। परंतु मध्य पूर्व में बनी अनिश्चितताओं ने इस तेजी को रोक दिया। निवेशक वैश्विक घटनाक्रमों को लेकर सतर्क बने रहे। इस सतर्कता के चलते बेंचमार्क सूचकांकों में बड़ी उछाल नहीं आ सकी। बाजार में निवेशकों ने सावधानीपूर्वक कारोबार किया। यह स्थिति वैश्विक तनाव के कारण बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में शुक्रवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला। एसएंडपी 500 वायदा में लंदन समय अनुसार सुबह 6:54 बजे तक बहुत कम बदलाव आया। नैस्डैक 100 वायदा में 0.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। एमएससीआई एशिया प्रशांत सूचकांक 0.7 फीसदी ऊपर रहा। एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में 0.9 फीसदी की वृद्धि हुई। जापान का टॉपिक्स सूचकांक लगभग अपरिवर्तित रहा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.3 फीसदी गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.8 फीसदी ऊपर चढ़ा। शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.2 फीसदी की गिरावट आई। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में भी बहुत कम बदलाव देखा गया। यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर बाजार में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। निवेशक विभिन्न भू-राजनीतिक और आर्थिक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं।

अल-नीनोः घटते आयात व कम पैदावार के चलते महंगी हो सकती हैं दालें, कीमत वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने कसी कमर

नई दिल्ली । अल-नीनो के खतरे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट की चिंताओं के बीच दालों के घटते आयात ने महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 70 फीसदी सूखे की आशंका जताई है, जो व्यापारियों के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए भी चिंताजनक है। हालांकि सरकार का कहना है कि दालों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भारत का दाल आयात घटकर 31.80 लाख टन रह गया, जो एक साल पहले के 32.27 लाख टन से 1.46 पीसदी कम है। इस अवधि के दौरान तुअर का आयात 5.05 लाख टन रहा। अधिकांश आपूर्ति मोजाम्बिक, तंजानिया और सूडान जैसे अफ्रीकी उत्पादक देशों से हुई। इस वर्ष जनवरी-जून के दौरान मोजाम्बिक 1.83 लाख टन से अधिक आपूर्ति के साथ तुअर का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। इसके बाद म्यांमार से 1.23 लाख टन, तंजानिया से 1.01 लाख टन और सूडान से लगभग 49,049 टन दाल का आयात हुआ। देश में प्रति वर्ष कुल दलहन उत्पादन 256.83 लाख टन है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चना दाल का करीब 40 फीसदी है। अरहर दाल का उत्पाद 15 से 20 फीसदी, जबकि उड़द व मूंग का 8 से 10 फीसदी हिस्सा है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 14 अगस्त तक देशभर में 108.14 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हो चुकी है। पिछले साल यह आंकड़ा 108.49 लाख हेक्टेयर था। इस लिहाज से दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 35 हजार हेक्टेयर कम है।

तुअर और मूंग की बुआई सबसे पीछे चल रही है। अरहर का रकबा अब तक 40.31 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 42.01 लाख हेक्टेयर की तुलना में 1.69 लाख हेक्टेयर कम है। मूंग का रकबा 32.05 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 33.42 लाख हेक्टेयर से 1.37 लाख हेक्टेयर कम है। उड़द, कुल्थी और मोंठ का रकबा पिछले साल के मुकाबले अधिक होने से दलहन के कुल रकबे की कमी का अंतर कम हुआ है। अन्य दालों का रकबा 14 अगस्त तक 3.14 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 3.40 लाख हेक्टेयर से 27 हजार हेक्टेयर पीछे है। खरीफ दालों की बुवाई 108 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो अच्छी रिकवरी दर्शाती है। हालांकि, मुख्य चिंता प्रति हेक्टेयर पैदावार को लेकर है। दालों की फसल को बीच के चरण में अच्छी बारिश की जरूरत होती है। अगस्त के अंत से सितंबर तक अल नीनो के मजबूत होने के संकेत हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर दालों की उत्पादकता पर पड़ सकता है। कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर व हेड ऑफ रिसर्च रवि देवड़ा का कहना है कि हाल के दिनों में चना 6,100 से बढ़कर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। उड़द और तुअर की कीमतें भी बढ़ी हैं, लेकिन ऊंचे आयात के कारण तुअर की कीमतों में एक सीमा तक ठहराव देखा गया। त्योहारी सीजन के दौरान मांग बढ़ेगी। जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दालों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सरकार ने लगभग 30 लाख टन दालों का बफर स्टॉक तैयार किया है। जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक से बाजार में दालों की आपूर्ति की जाएगी। इस बफर स्टॉक में अरहर, उड़द, मूंग, चना और मसूर शामिल हैं। सरकार बाजार की कीमतों पर लगातार नजर रखे हुए है।

एचडीएफसी बैंक ने कारोबार वृद्धि के लिए विदेशी बॉन्ड से जुटाए 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर

नई दिल्ली । एचडीएफसी बैंक ने अपनी कारोबार वृद्धि को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बैंक ने विदेशी बॉन्ड के माध्यम से 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर की बड़ी पूंजी जुटाई है। यह राशि बैंक के विस्तार योजनाओं को वित्तपोषण करने में मदद करेगी। बैंक ने नियामक जानकारी में बताया कि यह निर्गम जीआईएफटी सिटी शाखा के माध्यम से पूरा किया गया है। जारी किए गए बॉन्ड वरिष्ठ असुरक्षित श्रेणी के हैं। निजी क्षेत्र के इस प्रमुख ऋणदाता ने दो अलग-अलग बॉन्ड जारी किए हैं। पहले बॉन्ड से 500 दस लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं। इसकी कूपन दर 5.159 फीसदी है और यह तीन वर्ष में परिपक्व होगा। शेष 1.25 अरब अमेरिकी डॉलर पांच वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इस बॉन्ड पर 5.4 फीसदी की कूपन दर लागू होगी। इन बॉन्ड को इंडिया आईएनएक्स और एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाएगा। यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। एचडीएफसी बैंक ने अपनी कारोबार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यह पूंजी जुटाई है। बैंक अपनी ऋण देने की क्षमता का विस्तार करना चाहता है। इससे ग्राहकों को अधिक वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। यह पूंजी बैंक को नए बाजारों में प्रवेश करने में भी सहायता करेगी। बैंक की दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाओं के लिए यह निवेश महत्वपूर्ण है। बैंक ने कुल 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर के वरिष्ठ असुरक्षित बॉन्ड जारी किए हैं। इसमें 500 दस लाख अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड की परिपक्वता अवधि तीन वर्ष है। इन बॉन्ड पर 5.159 फीसदी की कूपन दर मिलेगी। वहीं, 1.25 अरब अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड पांच वर्ष में परिपक्व होंगे। इन पर 5.4 फीसदी की कूपन दर लागू होगी। ये सभी बॉन्ड इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड और एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसई-आईएक्स) पर सूचीबद्ध होंगे।

अगस्त में सुस्त पड़े विनिर्माण क्षेत्र को मिला सेवा क्षेत्र का सहारा, क्या रिकवर कर रहा निजी क्षेत्र

नई दिल्ली । भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अगस्त का महीना एक मिली-जुली राहत लेकर आया है। जुलाई में चार साल के सबसे निचले स्तर पर गिरने के बाद, अगस्त में भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियों में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह सेवा क्षेत्र (सर्विसेज सेक्टर) में आई तेजी है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई मंदी के असर को संभाल लिया है। एचएसबीसी के ताजा फ्लैश परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में कंपोजिट पीएमआई मामूली रूप से बढ़कर 54.6 पर पहुंच गया है, जो जुलाई में 54.3 था। यह आंकड़ा देश के आर्थिक मोर्चे पर चल रही हलचल और आगामी दिशा को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगस्त महीने के लिए जारी एचएसबीसी फ्लैश कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स लगातार 61वें महीने 50 के स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो भारतीय प्राइवेट सेक्टर में निरंतर हो रहे विस्तार को दर्शाता है (क्योंकि पीएमआई में 50 से ऊपर का अंक विस्तार और इससे नीचे का अंक संकुचन का प्रतीक माना जाता है)। हालांकि, जुलाई के 54.3 के स्तर के मुकाबले मामूली सुधार होने के बावजूद अगस्त का 54.6 का यह आंकड़ा मार्च 2022 के बाद से अब तक का दूसरा सबसे कमजोर प्रदर्शन भी है।

यह दिखाता है कि यद्यपि सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन घरेलू व्यापारिक गतिविधियों की रफ्तार अभी भी ऐतिहासिक औसत के मुकाबले सुस्त बनी हुई है। अगस्त के पीएमआई आंकड़े निजी क्षेत्र के दो सबसे बड़े स्तंभों के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाते हैंः सेवा क्षेत्र में शानदार रिकवरीः फ्लैश इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अगस्त में सुधरकर 54.5 पर पहुंच गया, जो जुलाई में 53.3 था। जुलाई में इस क्षेत्र में पिछले 53 महीनों की सबसे सुस्त वृद्धि देखी गई थी, लेकिन अगस्त में इसमें सराहनीय सुधार देखने को मिला है। विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में सुस्तीः इसके विपरीत, देश का विनिर्माण क्षेत्र अगस्त में कमजोर पड़ता दिखा। फ्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई के 53.5 से गिरकर अगस्त में 52.9 के स्तर पर आ गया। यह विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन और नए ऑर्डर्स के स्तर पर पिछले पांच वर्षों की सबसे धीमी वृद्धि दर है। रोजगार सृजन और इनपुट लागत पर इन बदलावों का क्या प्रभाव पड़ा है? व्यावसायिक गतिविधियों में आई इस मिली-जुली तेजी का सीधा प्रभाव नौकरियों और लागत पर पड़ा है। अगस्त में कंपनियों ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई भर्तियां की हैं, जिससे कुल रोजगार सृजन में सुधार हुआ है, लेकिन यह तेजी पूरी तरह से सेवा क्षेत्र तक ही सीमित रही। इसके विपरीत, विनिर्माण क्षेत्र में पिछले ढाई वर्षों में पहली बार कर्मियों की संख्या (स्टाफिंग लेवल्स) में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ, कंपनियों के लिए राहत की बात यह है कि इनपुट लागत (कच्चे माल की कीमत) की वृद्धि दर पिछले सात महीनों में सबसे धीमी दर्ज की गई है, जिससे लागत का दबाव थोड़ा कम हुआ है। एचएसबीसी की मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने इन आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करते हुए कहा, 'मजबूत सेवा गतिविधियों की मदद से कुल मिलाकर देश के प्राइवेट सेक्टर का उत्पादन काफी हद तक स्थिर बना हुआ है।' हालांकि, उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती पर चिंता जताते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार अगस्त में पांच वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे जोड़ा, 'यद्यपि कंपनियों पर लागत का दबाव कम हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए अंतिम सेलिंग प्राइसेज को अधिक तेजी से बढ़ाया है, जो यह दर्शाता है कि कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालने (पास-थ्रू) में मजबूत स्थिति में हैं। 'अगस्त के ये फ्लैश पीएमआई आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर मंदी की गहरी आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए धीरे-धीरे रिकवरी की राह पर बढ़ रहा है। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आई सुस्ती और विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में आई गिरावट नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी की तरह है। अब आगामी त्योहारी सीजन पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि फेस्टिव डिमांड ही तय करेगी कि क्या सर्विसेज सेक्टर की यह तेजी बनी रहेगी और क्या सुस्त पड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अपनी पुरानी रफ्तार को दोबारा हासिल कर पाएगा।